

हुए हैं उनमें से कितने बन चुके हैं और कितनों पर निर्माण-कार्य चल रहा है तथा कबतक वह पूरे हो जायेंगे ? अलीगढ़ में 80,000 एकड़ भूमि उत्तर है उसके लिए कितने ट्यूबवेल मंजूर हुए हैं ? कितने ट्यूबवेल बकिंग आर्डर में हैं और कितने कबतक बन जायेंगे ?

MR. SPEAKER: That is a good suggestion, but that is not covered by this question.

श्री चन्द्र पाल शैलानी : मैं यह इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर प्रापर ट्यूबवेल्स की व्यवस्था हो जाए तो अलीगढ़ में जो 80,000 एकड़ भूमि उत्तर है उसपर हरी-भरी फसल उग सकेगी। हसाइन ब्लाक में जहाँ सरकारी ट्यूबवेल की बहुत कमी है, दुनिया का सबसे अच्छा गुलाब पैदा होता है और अगर वहाँ पर ट्यूबवेलों के द्वारा पानी की व्यवस्था हो जाए तो विदेशी मुद्रा भी पर्याप्त मात्रा में अर्जित की जा सकती है और वहाँ की आर्थिक स्थिति भी सुधर सकती है।

SHRI R.V. SWAMINATHAN : This is only a pilot project. It is to be spread over 12 districts in the western, eastern and central parts of U.P. This project is to start from 1st April, 1980. So far as Aligarh is concerned, we are giving 40 tubewells. So, why do you worry ?

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: May I know how many wells were successful in U.P.

SHRI R.V. SWAMINATHAN A total of 15,283 tubewells have been put up, and all the tubewells are successful in U.P.

बिहार के जिला मुंगेर में गंगा के जल द्वारा गांव का कटाव

*190. श्रीमती कृष्णा झाही : क्या उज्ज्व और सिंचाई तथा कायला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला मुंगेर में बड़ाहिया पुलिस थाना के अन्तर्गत लगभग 30 हजार की जनसंख्या वाले गांव खुटाहा का गंगा नदी के जल द्वारा कटाव हो गया है ;

(ख) क्या उसी मंचल के 28 अन्य गांवों पर भी कटाव का प्रभाव पड़ा है परन्तु उनके पुनर्वास के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अब सरकार का विचार कटाव द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने का है ?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURY):

(a) to (c). A statement is placed on the Table of the House.

Statement

To erosion of villages in Monghyr district of Bihar by Ganga Waters

(a) Erosion of banks of river Ganga has been taking place in the Barahaiya-Khutaha area since 1974-75. Measures to prevent bank erosion were taken up in 1975 after the matter had been examined in detail by technical experts. These works included the construction of bed-bars, sal-ballah piling, boulder pitching, etc. Additional works have been recommended from time to time by a committee of experts which periodically inspects the area. The river bank has been protected by a revetment in some portion of the bank near Khutaha, but as the erosion is travelling to downstream areas, the extension of the revetment of another 1,000 ft. has been recommended by the Committee after its last inspection in December, 1979. The State Government has informed that this work is expected to cost nearly Rs. 34 lakhs in Khutaha area and further works amounting to nearly Rs. 70 lakhs will have to be constructed in Barahaiya area.

(b)&(c). Information regarding the number of villages affected by erosion and the arrangements if any, made or contemplated for rehabilitation is awaited from the Bihar Government.

श्रीमती कृष्णा झाही: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि गंगा नदी के द्वारा मुंगेर जिले के जिन गांवों का कटाव हुआ है उसका एरियल सर्वे भारत सरकार ने करवाया था, मंत्री महोदय ने भी अपने स्टेटमन्ट में कहा कि टोक्निकल एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की थी और जियोफिजिकल सर्वे का डाटा आई.आई.टी., लड़गपुर में है और जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया में प्राप्त है तो क्या उसके आधार पर भारत सरकार कोई कार्यवाही कर रही है?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I do not know whether an aerial survey has been done or not. Actually, this is a flood control measure and is a State subject. It is not even a Concurrent subject. They prepare schemes and send them for our approval. In this particular case, the entire scheme has been prepared by the State. From time to time, our experts have gone there to help them.

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा था कि भारत सरकार ने हाइड्रोलॉजिकल और जीओफिजिकल सर्वे कराया था, जिस की रिपोर्ट आई. वाई. टी. सड़गपुर और जिवालाजिकल सर्वे आफ इण्डिया के पास है। जब यह रिपोर्ट इन संस्थानों के पास है तो उस के आधार पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I do not have any information.

MR. SPEAKER: He says that he has no knowledge of such report.

श्रीमती कृष्णा साही : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि बिहार में 300 करोड़ रुपये की क्षति बाढ़ से होती है और उस में से 120 करोड़ रुपये की क्षतिमान मुंगेर जिले में होती है ? क्या उस के आधार पर भारत सरकार कोई कम्पेन्सेशन देने जा रही है ?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I have already said that this is a State subject altogether. The Government of India does not give any compensation.

श्री डी. पी. यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिल्कुल तैयारी करके नहीं आये हैं। किस मंत्रालय ने क्या काम किया है, शायद इस की पूरी जानकारी उन को नहीं है। अभी परसों ही लोक सभा में यह रिपोर्ट रखी गई थी—यह राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट है। इस में लिखा गया है कि भारत में जितना डैमेज फ्लड से होता है, उस का 23 प्रतिशत बिहार में होता है और बिहार में जितना नुकसान होता है, उस का 40 प्रतिशत केवल मुंगेर जिले में होता है। यह इस रिपोर्ट में कहा गया है—जिस का सम्बन्ध आप के

मंत्रालय से है। मैं आप से जानना चाहता हूँ कि बिहार में और विशेष कर मुंगेर में जो क्षति होती है, उस के लिये क्या आप कोई स्पेशल मेजर्स लेने जा रहे हैं ?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI: That is just a recommendation. All over India there is an erosion. What happens is this, normally, the funds required for flood control schemes are provided in the State Plans. In respect of important and emergent schemes, due consideration is given at the time of formulating the actual State Plan to see that adequate provision is made by the State Government for such schemes. In special cases, the Government of India sometimes consider giving loan assistance. For Bihar, advance Plan assistance was provided for Patna flood protection work. In regard to Monghyr, nothing was provided for.

MR. SPEAKER: He wants special attention for Monghyr.

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI: As I have said, we will consider it. But this is more a responsibility of the State than that of Centre.

श्री भारद्वाज राय: मान्यवर, विशेषज्ञों की इस राय को ध्यान में रख कर कि बड़ी-बड़ी इस राय को ध्यान में रख कर कि बड़ी-बड़ी नदियों में बाढ़ इस लिये ज्यादा आ रही है कि नदियों के किनारों पर जंगलों को काट दिया गया है, नदियों के पानी-तट तक खेत बना हर जुताई बुआई होती है; हर साल बरसात में मिट्टी बहकर नदी में चली जाती है; नदियों का पेटा ऊंचा होता जाता है, इसलिये बाढ़ ज्यादा आ रही है। क्या उपरोक्त तथ्य की रोशनी में सरकार कम से कम भारत की बड़ी-बड़ी नदियों के किनारों के दोनों तरफ दो-दो, तीन-तीन मील तक जंगल और घास लगाने की योजना पर विचार कर रही है जिस से मिट्टी न बहे, और बाढ़ को रोका जा सके ?

SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI: I know that it is a national problem. But it is a State subject.

श्री राम बिसास पासवान: बाढ़ के कटाव से प्रति वर्ष जो नुकसान होता है, उस में

सब के पुनर्वास की व्यवस्था तो आप नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या भारत सरकार के पास कोई ऐसी योजना है कि जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं उनके लिए व्यापक पैमाने पर पुनर्वास की योजना तैयार की जाय? यदि इस तरह की नीति पहले से है, तो बिहार में कितने भूमिहीन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: We have no scheme like that. If the State Government approaches us on this, we will consider it sympathetically.

श्री राम बिलास पासवान: मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है। आप प्रश्न के तीसरे खंड को देखिये। इस में लिखा हुआ है, यदि हां, तो क्या अब सरकार का विचार कटाव द्वारा प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने का है ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: As I said, we do not have any scheme like that. But if the State Government approaches us, the Central Government will certainly consider it.

श्री राम बिलास पासवान: मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से यह सूचना मंगवाई है कि कितने लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है ? आप ने स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में इन्फार्मेशन मंगवाई है ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI: As I have already said, we do not receive any reports from the State Governments. The Central Government does not provide any funds. The Central Government does not have any scheme like that. But if the State Government approaches us, we will certainly consider it.

डा. राजेन्द्र कुमार बाजपेयी: अध्यक्ष जी, प्रत्येक वर्ष बाढ़ से जो अलग-अलग जगहों पर नुकसान होता है, उस में मुंगेर जिले में 40 परसेंट कटान और तरह-तरह की बरबादी होती है। यह एक फाँट है और इसी तरह से दूसरी जगहों पर जब भी बाढ़ आती है तो नुकसान होता है और उस के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एक टोम जाती है और उस को देखती है। फिर स्टेट गवर्नमेंट

सेन्ट्रल गवर्नमेंट से मांग करती है और तब वह उस की मदद करती है। तो यह एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि मुंगेर जिले में जहाँ इतनी बड़ी बरबादी हो रही है, इतना जमीन का कटान हो रहा है, तो क्या सरकार एक ऐसी योजना बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहेगी कि यह बरबादी रुके या अपनी टीम भेज कर कोई योजना बनावें ताकि जो इतनी ह्यूमन मिजरी का इश्ये हर साल दिखाई देता है, वह समाप्त हो और सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी हर साल करोड़ों और अरबों रुपया इस पर खर्च करती है ? सेन्ट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ऐसी योजना क्यों नहीं बनवाती है ?

MR. SPEAKER This question has already been answered.

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: I would like to draw the attention of the hon. Minister to the statement laid on the Table of the House in reply to this specific Question. It does not indicate whether any rehabilitation measure has been undertaken in respect of these villages. I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that this problem has arisen in this area because of the construction of the railway bridge at Mokama. In view of this, would the Government of India give us an assurance that it would take interest not only in the scheme for anti-erosion work and rehabilitation work but also give financial support to this scheme.

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI I have already explained that.

Increase in Price of Coal after Nationalisation

*191. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of ENERGY AND IRRIGATION AND COAL be pleased to state on how many occasions since nationalisation the price of coal was raised and what percentage increase in the prices of coal has been effected since nationalisation ?

THE MINISTER OF ENERGY AND IRRIGATION AND COAL (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHAUDHURI): The price of coal has been increased thrice since its nationalisation. The increase in the pit head price of coal after the last price revision with effect from 17-7-1979, as compared to pit head price at the time of nationalisation of coal industry is 170%.